में आदिवासियों को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं ।

(ग) देश में पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के उद्देश्य से देश में वन क्षेत्रों की सुरक्षा तथा वन क्षेत्र में हो रही कमी को रोकने के लिए सरकार ने निम्न लिखित कार्रवाई की है :—

1. दिसम्बर, 1988 में एक नयी-राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गयी थी, जिसमें वनों के संरक्षण पर अधिक बल दिया गया है । इसमें चराई, अग्नि और अवैध कब्जों से वनों की सुरक्षा के लिए विशेष उपबंध है ।

2. गैर-वन प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग को रोकने के लिए 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया था । 1988 में एक संशोधन करके इस अधिनियम को और अधिक कठोर बनाया गया है ।

3. वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए राज्यों को सहायता देने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम शुरू की गई है ।

4. घरेलू और वाणिज्यक क्षेत्रों में ऊर्जा के लिए ईंधन की लकड़ी के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहन दिया जाता है ।

5. पैकिंग, रेलवे स्लीपरों, भवन निर्माण और फर्नीचर आदि में लकड़ी के विकल्पों का उपयोग किया जा रहा है ।

6. इमारती लकड़ी के लिए आयात नीति को उदार बना दिया गया है ।

7. झूम खेती को नियंत्रित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

8. वनों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । इनमें से कुछ दिशा-निर्देश नीचे दिए जाते हैं :—

(1) प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई से बचना और जहां फसलों की बहाली अथवा अन्य बागबानी दृष्टकोणों से, इस प्रकार की कटाई जरूरी हो, वहां पहाड़ों पर इसका क्षेत्र 10 हैक्टेयर और मैदानों में 25 हैक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(2) पहाड़ों पर 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की कटाई पर कम से कम कुछ सालों के लिए प्रतिबंध लगाने का विचार करना ।

(3) पहाड़ियों और पर्वतों पर उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें कटाई से वनों की सुरक्षा करने और और तत्काल व्यापक वन रोपण की जरूरत है ।

(4) 4 प्रतिशत भोगोलिक क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्यों राष्ट्रीय उद्यानों जीव मंडल रिजर्वों आदि जैसे सुरक्षा क्षेत्रों में सब में अलग रखना ।

(5) वनों को आग से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय करना ।

9. निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का दर्जा बढाकर राष्ट्रीय परती भूमि विकास मिशन कर दिया गया है :

—भू-अवक्रमण को रोकना

—परती भूमि का स्थाई उपयोग करना

—बायोमास, विशेष रूप से ईंधन की लकड़ी/चारे की उपलब्धता में वृद्धि करना और

—पारिस्थितिकीय संतुलन की बहाली

Swedish Audit Bureau Report on Payments n the Bofors Gun Deal

*29. SHRI ASHWANI KUMAR:

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to answer to Starred Question 208 given in the Rajya

Sabha on the 1st August, 1989 and state:

(a) whether the Swedish Audit Bureau had revealed in May-June, 1987 that huge payments had been made in secret Swiss Bank accounts by the Bofors in the Howitzer gun deal;

(b) whether the CBI had registered a criminal case; if so, when and for what offence and against whom;

(c) whether an Indian Court was approached to seek Swiss help for knowing about the recipients of the Bofors payments; if so, with what results; and if not, the reasons therefor; and

(d) whether an understanding has been reached with the Swiss Government to help each other in criminal cases like that of Bofors payments; if so, what specific steps have been taken to know the identity of the recipients?

THE PRIME MINISTER (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) A C.B.I. case, Preliminary Enquiry, was instituted on 8-11-1988, primarily against W. N. Chadha, M/s. Anatronic General Corporation, New Delhi, M/s. Svenska Inc. (a company incorporated in Panama) and others.

(c) and (d) So far no Indian Court has been approached. Assistance has been sought by CBI by sending a Letter Rogatory in terms of the Memorandum of Understanding with the Swiss Government.

Rejection of Rice by Foreign Buyers

*30. SHRI ISH DUTT YADAV: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 1893 given in the Rajya Sabha on the 10th March, 1989 and state:

(a) what was the total quantity of rice rejected by the foreign buyers of NCCF, at Kandla Port during 1981-82, as being of inferior and sub-standard quality, apart from that damage due to the reported cyclone;

(b) what was the exact amount of rebate given per M/T, in U.S. dollars, on this rejected quantity of rice; and

(c) what disciplinary action had been taken against the concerned Regional Manager and his staff for procuring and despatching this inferior and sub-standard quality of rice to Kandla, resulting in loss to the Federation?

THE MINISTER OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI NATHU RAM MIRDHA): (a) NCCF have reported that 10775 MTs. of IR-8 rice and 7073 MTs. of PR-106 rice were found to be containing higher broken percentage and consequently could not be loaded to the ships before the rain and cyclone at the Kandla Port.

(b) The rebate of US $ 10.00 per M.T. was allowed for the shipment of 9552 MTs. of IR-8 rice as per records of NCCF.

(c) The stocks were certified to be export worthy as per the specifications of foreign buyer at the procuring centres. The stocks were rejected mainly on account of higher broken percentages which was due to prolonged storage in the open space at Kandla Port in extreme heat, on account of delay in nomination of vessels by the foreign buyers, congestion in Kandla Port and non-receipt of polythene packing bags from the importers' agent.

No action has been taken against the then Regional Manager (N) and the staff in this matter.

The NCCF have filed a case in the High Court of Delhi against the Insurance Company and the matter is sub-judice.